देश की ज़िद
कोरोना को
हराना है

डेमोक्रेटिक फ्रंट

पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित

देश की ज़िद
कोरोना को
हराना है

दिनाक : 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022, अंक-2, वर्ष-1

लोकतंत्र की आवाज

Email : democraticfront2021@gmail.com | democraticfront.com | RNI: HARMIN11362 | मूल्य : 2 रुपये

राजपथ पर रोमांच पैदा करेंगे राफेल

आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस बार की गणतंत्र दिवस परेड सबसे भव्य ही नहीं, सबसे बड़ी भी होगी। इसमें 75 लड़ाकू विमान राजपथ पर उड़ान भरते हुए देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के जश्न को यादगार बनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में 75 लड़ाकू विमान राजपथ पर उड़ान भरते हुए देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के जश्न को यादगार बनाएंगे। जाहिर है गणतंत्र दिवस परेड बेहद भव?य होने वाली है. वायुसेना के सबसे आधुनिक विमान राफेल और सुखोई, मिग और जगुआर ही नहीं, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले ड्रोनियर और डकोटा विमान भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगे।राजपथ पर लड़ाकू विमानों के सबसे बड़े फ्लाई पास्ट में केवल वायुसेना ही नहीं, बल्कि सेना और नौसेना के विमान भी शामिल रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की चुनौतियों के बीच आजादी के अमृत वर्ष के मौके पर हो रहे गणतंत्र दिवस समारोह को खास बनाने के लिए वायुसेना ने विशेष रूप से अमृत फार्मेशन तैयार किया है। परेड के आखिरी हिस्से में 75 का स्वरूप बनाते हुए सात जगुआर विमान यह समारोह अमृत महोत्सव को समर्पित करते नजर आएंगे।गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े फ्लाई पास्ट में इस बार राजपथ पर अलग-अलग कुल 16 फार्मेशन होंगे। परेड की तैयारियों को लेकर वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि फ्लाइपास्ट दो हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में चार एमआइ 17वी5 हेलीकाप्टर का तिरंगा लिए ध्वज फार्मेशन होगा, जिसमें तीनों सेनाओं के झंडे भी लहरा रहे होंगे। दूसरे में चार एडवांस लाइट हेलीकाप्टर डायमंड फार्मेशन बनाएंगे।इसके बाद राजपथ पर थलसेना और सुरक्षा बलों का मार्च पास्ट तथा झांकियां निकलेंगी। परेड के आखिरी हिस्से में वायुसेना राजपथ पर 75 विमानों से सजे फ्लाई पास्ट को अंजाम देगी। इसमें वायुसेना के सात राफेल जेट भी शामिल होंगे। दुश्मन को कठोर संदेश देने के लिए विनाश फार्मेशन में पांच राफेल होंगे। वहीं दो सुखोई, दो मिग और एक राफेल मिलकर बाज फार्मेशन से राजपथ को रूबरू कराएंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में 75 लड़ाकू विमान राजपथ पर उड़ान भरते हुए देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के जश्न को यादगार बनाएंगे। जाहिर है गणतंत्र दिवस परेड बेहद भव्य होने वाली है

अमृत फार्मेशन से ठीक पहले एक राफेल विजय के स्वरूप की झलक दिखाएगा। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान 1971 में पाकिस्तान से जंग के निर्णायक मोर्चा टंगेल को समर्पित इस नाम के फार्मेशन में पुराने डकोटा और ड्रोनियर विमान रहेंगे। डकोटा एयरक्राफ्ट से ही ढाका के करीब टंगेल में भारतीय सेना ने सैनिकों को एयर-ड्राप कर पाकिस्तानी सेना की घेरेबंदी की थी और उसे आत्मसमर्पण को बाध्य कर दिया था।फ्लाई पास्ट में नेत्र फार्मेशन में एक अवाक्स टोही विमान और दो-दो सुखोई और मिग-29 लड़ाकू जेट होंगे। सुखोई लड़ाकू विमान त्रिशूल फार्मेशन और एमआइ 17 तथा चिनूक हेलीकाप्टर मिलकर मेघना फार्मेशन बनाएंगे। फ्लाई पास्ट में नौसेना के पी8आइ एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और मिग-29 फाइटर जेट वरुणा फार्मेशन का स्वरूप दिखाएंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में 75 लड़ाकू विमान राजपथ पर उड़ान भरते हुए देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के जश्न को यादगार बनाएंगे। जाहिर है गणतंत्र दिवस परेड बेहद भव्य होने वाली है

केजरीवाल थूककर चाटने वाले, गिरगिट.. नवजोत सिद्धू ने फिर बोला तीखा हमला

चंडीगढ़/(एजेंसी)। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल को गिरगिट और थूक के चाटने वाला बताया है। इसके अलावा उनके ऊपर नकल करने का भी आरोप लगाया। सिद्धू ने ये आरोप एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान दिल्ली सीएम पर लगाए। सिद्धू ने कहा कि नाम से बड़ी संपदा कोई और नहीं है। नाम ही प्रेरणा होती है। बाबा ने मुझे एक ही चीज सिखाई. जिन्होंने वोट दिया उनका विश्वास न टूटे। राजनीति धंधा नहीं होनी चाहिए। गंदी हो गई है, मैली हो गई है। अगर चरित्र अच्छा है तो सफेद चादर लेकर काजल की कोठरी से भी बाहर निकला जा सकता है। सिद्धू ने कहा कि उन्हें पंजाब की जनता पर विश्वास है। अगर विश्वास था तभी छह इलेक्शन जीते, विश्वास था तभी प्रदेश अध्यक्ष बने। जमीन फाड़कर जब आवाज आती है तो सुननी पड़ती है। आज आवाज विश्वसनीयता की नहीं है। सिस्टम के खिलाफ, वादाखिलाफी और बदलाव की है। पंजाब का मॉडल गन्ने की तरह छोटा हो लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीठा हो। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को पंजाब मॉडल बना दिया। सिद्धू ने पंजाब मॉडल की बात की तो वह भी करने लगे। देवता कुएं की गहराई में भी हो तो वह देवता ही रहता है। सिद्धू ने धज्जियां उड़ा दीं तो उन्होंने पंजाब मॉडल की बात की।

सिद्धू ने कहा कि काले कानून नोटीफाई करने वाले सबसे पहले केजरीवाल ही थी। ड्रग्स की बात की। पिछली बार भी ड्रग्स की है बात की थी, हम ड्रग्स के तस्करों को जेल भेजेंगे। कहा लेकिन थूक कर चाटा, लेट के बड़े-बड़े तस्करों के सामने माफी मांगी। केजरीवाल के दोगुले मापदंड हैं।

गिरगिट भी इतनी जल्दी नहीं बदलता रंग

नवजोत सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने पहले कहा कि 26 लाख नौकरी दूंगा कहा था, इस बार कुछ और बोल गए। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता है। कहा 8 लाख नौकरी देंगे दिल्ली में 440 नौकरियां दीं।

शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए याद किए जाएंगे बिरजू महाराज: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जानेमाने कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के निधन पर सोमवार को दुख जताया और कहा कि वह शास्त्रीय नृत्य के लिए अपने योगदान को लेकर याद किए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, ''कथक नर्तक श्री बिरजू महाराज के निधन की दुखद खबर मिली। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है और इसके वह याद किए जाएंगे। बिरजू महाराज का सोमवार तड़के यहां अपने घर में निधन हो गया।

गैंगस्टर एक्ट के आरोपित नाहिद हसन को सपा से उम्मीदवार बनाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपित नाहिद हसन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफसे कैराना सीट से टिकट दिए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में मांग की है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के लिए अखिलेश यादव पर अवमानना का मुकदमा भी चले। उल्लेखनीय है कि शाहिद हसन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने कैराना विधानसभा से टिकट दिया था लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया और उनकी बहन इकरा को टिकट दिया है।

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा: धामी

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित किए जाने के बाद सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि वह अपने और परिवार के लिए टिकट का दबाव बना रहे थे। धामी के अनुसार, पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। राजधानी में पत्रकारों से चर्चा में धामी ने यह भी कहा कि रावत पहले भी कई मौकों पर पार्टी को असहज करते रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने हमेशा उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ''हमारी पार्टी विकासवाद और राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर रहने वाली पार्टी है। हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।''

मोदी विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे रात साढ़े आठ बजे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार भारतीय समयानुसार रात 08:30 बजे विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विश्व की वर्तमान स्थिति' पर विशेष संबोधन करेंगे। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह वर्चुअल कार्यक्रम 17 से 21 जनवरी तक चलेगा।

कार्यक्रम को जिन विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा संबोधित किया जाएगा, उनमें जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुआ वॉन डेर लेयेन , ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन , इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो , इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट , पीपुल्स रिपब्लिक ऑफचाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग तथा अन्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज भी भाग लेंगे, जो दुनिया की वर्त्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

उम्मीद है पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष दो हफ्ते में मुकुल रॉय पर फैसला लेंगे: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष दो सप्ताह में मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए दी गई अर्जी पर फैसला कर लेंगे। मुकुल रॉय राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। न्यायमूर्ति एल नगेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दी। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे सप्ताह तक टाल दी जाए क्योंकि सख्त समय सीमा तय करना व्यवहारिक नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने हालांकि, मामले की सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह तक टाली और कहा कि वह उम्मीद करती है कि समय पर फैसला होगा। पीठ ने कहा, ''हम उन्हें दो सप्ताह का समय देंगे। मामले को सुनवाई के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह सूचीबद्ध करे। इस बीच सुनिश्चित करें कि यह पूरा हो, हम आदेश में वह नहीं कह रहे हैं।'' शीर्ष अदालत दो अलग-अलग अपील पर सुनवाई कर रही थी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी और उनके सचिव और पीठासीन अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफदाखिल की हैं।

एमजी रामचंद्रन की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- प्रभावी प्रशासक के रूप में किया जाता है याद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित एमजी रामचंद्रन की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमजीआर को एक प्रभावी प्रशासक के रूप में व्यापक तौर से सराहा जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एमजीआर की ओर से गरीबी को खत्म करने के लिए किए गए काम और महिला सशक्तीकरण के प्रयासों की सराहना की। पीएम ने कहा कि एमजीआर ने सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण को हमेशा अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा।प्रभावी प्रशासक के रूप में सराहे जाते हैं एमजीआर प्रधानमंत्री ने सोमवार को भारत रत्न एमजीआर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट कर कहा कि एमजीआर को

हमेशा प्रभावी प्रशासक के रूप में सराहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि एमजीआर ने अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने कहा कि एमजीआरस की सिनेमाई प्रतिभा भी लोगों में काफी चर्चित है। पीएम समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी एमजीआर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजली दी।कौन थे एमजी रामचंद्र आपको बता दें कि एमजी रामचंद्रन का जन्म 17 जनवरी 1917 में नवलपिट्टिया में हुआ था। नवलपिट्टिया श्रीलंका की सीमा में आता है। इसके साथ ही उनको अभिनय का काफी शौक था। उन्होंने अपने स्कूल में ही एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया था और वह तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। उन्होंने 30 सालों तक तमिल सिनेमा में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के संस्थापक भी थे। उन्होंने 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 10 सालों तक काम किया। 1987 में एमजीआर का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था।

कोरोना की इस तीसरी लहर से कब तक मिल पाएगी राहत क्या कहते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर

ओमिक्रोन वैरिएंट के कारण राजधानी में कोरोना के नए मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद अब इनमें कमी आने लगी है। हालांकि, संक्रमण दर में खास कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यह तीसरी लहर के थमने का संकेत है या नहीं। इसको लेकर सफदरजंग अस्पताल में प्रिवेंटिव कम्युनिटी मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर डा. जुगल किशोर ने अपने विचार रखें। उनके हिसाब से जानिए अभी और कितने दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद है।सवाल- तीन दिन से कोरोना के मामले घट रहे हैं लेकिन संक्रमण दर खास नहीं घटी है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं?

जवाब- बिल्कुल इसे राहत की बात माना जा सकता है, क्योंकि पहले जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे थे, उसी तेजी के साथ संक्रमण दर भी बढ़ रही थी। चूंकि अब यह स्थिर है, इसलिए आने वाले दिनों में संक्रमण दर में कमी आएगी तो मामले और भी कम आएंगे। इसलिए कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर घटना दोनों राहत की बात है।सवाल- आइसीएमआर के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना लक्षण वाले लोगों की जांच बंद कर दी गई है, क्या इस वजह से मामले कम हुए हैं

जवाब- आइसीएमआर द्वारा बहुत पहले ही यह कदम उठाया जाना चाहिए था। ओमिक्रोन का संक्रमण इतना हल्का है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए जांच कराना पहले से ही जरूरी नहीं था। अधिक जांच कराने की वजह से ही अधिक मामले आ रहे थे।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एनटीएजीआई के चेयरमैन ने दिया बड़ा संकेत

मार्च से शुरू हो सकता है 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्यसमूह के अध्यक्ष डा. एनके अरोड़ा ने बताया कि के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है क्योंकि तब तक 15 से 18 आयुवर्ग के किशोरों के पूरी तरह से टीकाकरण पूरा हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग में अनुमानित आबादी 7.5 करोड़ है।3.45 करोड़ से अधिक किशोरों को दी जा चुकी है पहली खुराक

मालूम हो कि इस साल तीन जनवरी को 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू किया गया था। डा. एनके अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि 15 से 18 साल के अनुमानित 7,40,57,000 किशोरों की आबादी में से 3.45 करोड़ से अधिक को अब तक कोविड रोधी वैक?सीन कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इनको 28 दिनों में दूसरी खुराक दी जानी है। इस आयु वर्ग के किशोर में टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है।सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

डा. एनके अरोड़ा ने कहा कि किशोरों के टीकाकरण की इस गति को देखते हुए 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के शेष लाभार्थियों को जनवरी के अंत तक पहली खुराक लग जाने की संभावना है। इसके बाद किशोरों को दूसरी खुराक फरवरी के अंत तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। 15 से 18 वर्ष के

- **एनटीएजीआई के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डा. एनके अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना है क्योंकि तब तक 15 से 18 आयुवर्ग के किशोरों के पूरी तरह से टीकाकरण पूरा हो जाने की संभावना है।**

किशोरों का टीकाकरण पूरा हो जाने के बाद सरकार मार्च में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू करने पर नीतिगत फैसला कर सकती है।

ऐसे बढ़ता गया अभियान बता दें कि 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के साथ ही देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। यही नहीं दो फरवरी 2021 को फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाने की शुरुआत हुई। यही नहीं एक मार्च 2021 को 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर रोगों से ग्रस्त 45-60 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया था। पिछले साल एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक?सीन दी जानी शुरू की गई थी। पिछले साल एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ था।टीकाकरण के अहम पड़ाव

मालूम हो कि इस साल 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर रोगों से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र वालों को सतर्कता डोज देनी शुरू की गई थी। यदि टीकाकरण के अहम पड़ावों पर गौर करें तो पिछले साल एक अप्रैल तक देश में 10 करोड़ डोज लगाई गई थीं। पिछले ही साल 21 अक्टूबर को 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया गया था। इस साल सात जनवरी को 150 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया गया था।

प्रादेशिक क्रियाकलापों और प्रत्याशी की छवि पर आधारित होंगे विधानसभाओं के चुनाव

देश के पांच राज्यों में चुनावी दुन्दुभी बज चुकी है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर में ढिढुरती ठंड में भी राजनैतिक तापमान बेहद बढा हुआ है। दलबदलू लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ चरम सीमा पर दिखने लगा है। लालच के वशीभूत होकर सिध्दान्तों को तिलांजलि दी जा रही है। आदर्शों पर जीवन निछावर करने वाली धरती पर मान्यताओं की होली जलाने वालों की बढ सी आ गई है। स्वयं, परिवार और अपनों तक सीमित रहने वाले धनबलियों ने स्वयं भू ठेकेदार होने की नई परम्परा की शुरूआत कर दी है। भौतिक संसाधनों की होड में लगे लोगों ने शारीरिक सुख की चाहत में वास्तविक आनन्द को तिलांजलि दे दी है। कुछ अपवाद स्वरूप नागरिकों को यदि अदृष्टिगत कर दें तो देश के अधिकांश लोगों में मृगमारीचिका के पीछे भागने की होड लगी है। यूं तो पांच राज्यों में सत्ता हथियाने वालों ने चालों पर चालें चलना शुरू कर दी हैं परन्तु उत्तरप्रदेश, पंजाब और उत्तराखण्ड का दंगल निरंतर सुर्खियों में है। कोरोना काल में सुरक्षात्मक निर्देशों की धज्जियां उडाने की घटनायें निरंतर सामने आ रहीं है। समर्थन का प्रदर्शन करने के क्रम में लोगों की जान को खतरे में डालने वालों का नेतृत्व आने वाले समय में किस रूप में होगा, यह तो भविष्य ही निर्धारित करेगा परन्तु वर्तमान में बिना मांगे बीमारियों की तत्काल सौगात मिलने की संभावना बेहद अधिक है। दलगत राजनीति का उदय मानवीय सिध्दान्तों, आदर्शो और मान्यताओं की विभिन्नताओं के आधार पर हुआ था। राष्ट्रीय स्वधीनता के आधार पर गठित की गई पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद उसे राजनैतिक दल में परिवर्तित करके अतीत की दुहाई देना शुरू कर दी थी। तब समानान्तर रूप से विपरीत कारकों के समुच्चय को लेकर एक अन्य दल ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। विदेशी घरती से लाल सलाम का आगाज हुआ। मजदूरों, किसानों और कामगारों को उनके हितों की रक्षा का सब्जबाग दिखाया गया। कालान्तर में छात्रों, कलाकारों और संवेदनशील बुध्दिजीवियों तक के मध्य सैध्दान्तिक खाई खोदने का प्रपंच भी रचा गया। इसके बाद व्यक्तिगत हितों, स्वार्थों और विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृति के आधार पर अनेक पार्टियों ने दस्तक दी। विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र की अनेक पार्टियां आज सामंतशाही की राह पर चल रहीं हैं। परिवारवाद के मकडजाल में फंसे दलों के नेतृत्व के पीछे चाटुकारों की एक लम्बी फौज खडी हो गई। बंद कमरों में अहम की पौध पनपाई जाने लगी। पैत्रिक धरोहर के रूप में नेतृत्व कर रहे परिवारों में भी वर्चस्व का युध्द सडकों पर अस्तित्व में आ गया। सामाजिक ढांचे के स्तम्भों को तोडने वाले बहुमत हासिल करने लगे। वैमनुष्यता फैलाकर जातिगत मुद्दों को नारों में बदलकर सत्ता पाने वालों से लेकर सम्प्रदायगत वक्तव्यों का सहारा लेने वालों तक की लालसा केवल और केवल सत्ता पाने तक ही सीमित है। सभी जानते हैं कि कालीचरण के पडोस में रहने वाले रमजान मियां इन राजनैतिक व्देष की बिना पर कभीभी आपसी संबंधों को दर किनार नहीं करेंगें। दुःख, तकलीफ और मुसीबत के दौरान भडकाऊ भाषण देने वाले नेताजी उनका सहयोग करने के लिए तत्काल हाजिर नहीं होंगे, तब पडोसी ही कवच बनकर खडा होगा। मगर सोशल मीडिया के माध्यम से मनगढंत पोस्ट फैलाने वालों का गिरोह अपने आकाओं के इशारे पर देश में असुरक्षा का वातावरण जरूर तैयार कर रहा हैं। इस तरह के शगूफों के लिए सीमापार से खासी आर्थिक सहायता भेजी जाती है। चुनाव काल में तो दंगे-फसाद करवाने से लेकर

अफवाहों तक का बाजार चरम सीमा की ओर पहुंच जाता है।

चुनावी परिपेक्ष में जहां भाजपा को धारा 370 हटाने, राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्णय का करवाने, बनारस कैरीडोर बनवाने, कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन, खाद्य सामग्री का निःशुल्क वितरण, निर्धन आवास, किसान कल्याण जैसे कार्यो पर जनादेश मिलने की आशा है वहीं उसके व्दारा केवल उत्तरप्रदेश में ही जातिवाद के आधार पर क्षत्रियों को संरक्षण, ब्राह्मणों का उत्पीडन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की उपेक्षा के योगी फार्मूले से धराशाही होने का खतरा भी मडरा रहा है। पार्टी ने एक बार फिर योगी को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर एक बडी भूल की है, ऐसी चर्चा चौराहों से चौपालों तक सुनने में आ रही है। प्रदेश का मुसलमान योगी की व्यक्तिगत नीतियों का खुला आलोचक है। उसे मोदी की गम्भीरता पर तो विश्वास है परन्तु योगी का राजतिलक कदापि बर्दाश्त नहीं है। वह निर्विवाद रूप भाजपा के सशक्त होते विरोधी खेमे का ही दामन थामेगा।

प्रदेश में आम आवाम के पास विकल्प के रूप में केवल समाजवादी पार्टी ही दिख रही है परन्तु उसमें चुनावी मेंढकों की आमद होने से पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर करने लगे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत छवि के आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तालठोकने वालों को भी सफलता मिलने की संभावना बलवती हो जाती है। उत्तरप्रदेश के अलावा पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डालने वाला कृत्य, सत्तासीन कांग्रेस के सिध्दू की पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ यारी, पार्टी के असंतुष्ट खेमें का सक्रिय होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो चुनावों के परिणामों को सीधा प्रभावित करेंगे। अकाली दल, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों की वर्तमान घोषणाओं पर ही उसका जनाधार निर्धारित करेगा।

दूसरी ओर सीमापार से खालिस्तान समर्थकों को सहयोग देकर सक्रिय करने की चालें और किसान आंदोलन के नाम पर अनेक असामाजिक तत्वों की भीड ने खुशहाल पंजाब के माथे पर लकीरें गहरा दी है। छत्तीसगढ के बाद अब उत्तराखण्ड में संतों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी की नियत को उजागर कर दिया है। इस राज्य का राजस्व तीर्थ यात्रा पर आने वाले आगंतुक श्रध्दालुओं पर ही निर्भर रहता है। होटल, टैक्सी, गाइड, आवास, पूजा, दुकान, व्यापार, गैरेज जैसे अधिकांश व्यवसाय तो लम्बे समय से यात्रियों की आमद पर ही निर्भर रहते हैं। उसी राज्य में अब आस्था पर चोट करने का क्रम चल निकला है। आखिर यह किसकी संतुष्टि के लिए राज्य के श्रध्दामय वातावरण को धूल धूसित करने के षडयंत्र को अमली जामा पहनाया जा रहा है। गढवाल और कुमांऊ के निवासी तो पर्यटन पर निर्भर अपनी जीविका को लेकर खासे चिन्तित हैं। गोवा और मणिपुर में तो बहाव का प्रवाह चल निकला है। राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधुनिकता को थोपने के प्रयास करने वाले स्वयं को समाज के हितकारी बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में राज्यों के चुनावों में मोदी के नेतृत्व को आंखबंद करके स्वीकारने वाले मतदाता भी प्रदेश में भाजपा के वर्तमान कर्णधारों के क्रियाकलापों और प्रत्याशी के आधार पर ही मतदान का मन बना चुके है। कांग्रेस को तो अपने ही कम्युनिष्टीकरण का खामियाजा भुगतने की नौबत दिख रही है। पार्टी के पुराने दिग्गजों को दरकिनार करने वाले वर्तमान नेतृत्व की अनुभवहीनता और निज सहायक को तौर मौजूद बामपंथी विचारधारा के पोषितों के क्रियाकलापों ने परिवारवार की जडों को हिला कर रख दिया है। राष्ट्रीय पार्टियों के व्दारा क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया जा रहा है, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के मनोबल को सीधा प्रभावित करेगा। ऐसे में वर्तमान समीकरणों की विवेचना करने पर यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इस बार प्रादेशिक क्रियाकलापों और प्रत्याशी की छवि पर आधारित होंगे विधानसभाओं के चुनाव। पूरी तस्वीर तो आने वाले समय में ही साफहो सकेगी। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।

पाक की फितरत

सीमा पार से आतंकवाद फैलाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई भारत विरोधी साजिश में नए रास्तों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की कवायद में जुटी है। भारत में आतंक फैलाने के लिए पाक अब धर्म का रास्ता अख्तियार करने में जुटा है। करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ की आशंका भी खुफिया एजेंसियों ने जाहिर की है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने घुसपैठ की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा को सौंपी है। आईएसआई करतारपुर कॉरिडोर से आतंकियों को भारत भेजने के लिए दस्तावेज व सुविधाएं मुहैया कराएगी। खास मकसद के लिए आतंकियों को दो सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग आईएसआई की निगरानी में दी गई है। यह भी पता चला है कि आतंकी संगठन पांच लोगों के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, जो सिख पोशाक पहनेंगे। इस संगठन को साकरगढ़ में एक आतंकी शिविर में आईएसआई की निगरानी में दो सप्ताह का कमांडो प्रशिक्षण दिया गया है और यह लश्कर-ए-तंजीम संगठन से जुड़ा है। निकट भविष्य में घुसपैठ की यह कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान की तरफसे आतंक परस्त नीति अपनाए जाने की खबर आज पूरी दुनिया को है। यहां तक की जिस तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित करने में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बदनामी मोल ली, उसी ने पाक को आंखें दिखा दी है। दरअसल, तालिबान इस बार अपनी आतंक वाली नीति को पीछे छोडना चाहता है, मगर पाक को इसी में अपना हित दिख रहा है। यही वजह है कि आज दोनों देशों में ठन गई है।

संपादकीय

श्रीलंका पर चीनी घेरा

चीन के विदेश मंत्री वांग यी पिछले दिनों कुछ अफ्रीकी देशों के साथ-साथ श्रीलंका भी गए। वहां उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया लेकिन जो बयान दिया, उसमें उन्होंने साफसाफकहा कि चीन-श्रीलंका संबंधों में किसी तीसरे देश को टांग नहीं अड़ानी चाहिए।

यही बात उनके राजदूतावास ने उनके कोलंबो पहुंचने के पहले अपने एक बयान में कही थी।

श्रीलंका किसी भी राष्ट्र के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए, इसमें भारत को क्या आपत्ति हो सकती है लेकिन चीन की नीति यह रही है कि वह भारत के आस-पड़ोस में जितने भी राष्ट्र हैं, उनमें भारत-विरोध भड़काए। उसकी हरचंद कोशिश होती है कि वह भारत का कूटनीतिक घेराव कर ले। उसने पाकिस्तान के साथ इसीलिए 'इस्पाती दोस्ती' की घोषणा कर दी है।

भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं लेकिन उनकी भी कोशिश रहती है कि भारत-चीन प्रतिस्पर्धा को वे अपने लिए जितना दुह सकते हैं, दुहें। श्रीलंका इसका सबसे ठोस उदाहरण है। श्रीलंका के अनुरोध पर उसके आतंकवादियों से लड़ने के लिए भारत ने अपनी सेना वहां भेजी थी। हमारे लगभग 200 सिपाही भी कुरबान हुए थे। लेकिन श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्ष और उनके भाई और पूर्व राष्ट्रपति महिंद राजपक्ष ने सत्तारूढ़ होते ही चीन के साथ इतनी पींगे बढ़ा लीं कि अब श्रीलंका चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है। चीन की रेशम महापथ की महत्वाकांक्षी योजना का श्रीलंका अभिन्न अंग बन गया है। उसने अपने सुदूर दक्षिण के हंबनटोटा नामक बंदरगाह को अब चीन के हवाले ही कर दिया है, क्योंकि उसके लिए उधार लिये गए चीनी पैसे को वह चुका नहीं पा रहा था।

चीनी विदेश मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान समुद्री तटों पर बसे देशों के एक क्षेत्रीय संगठन का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य भारत द्वारा शुरू किए गए 'सागर' नामक क्षेत्रीय संगठन को टक्कर देना है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस खेल में श्रीलंका को चीन अपना मोहरा बना लेगा। इस समय श्रीलंका की आर्थिक स्थिति दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा खराब है। चीनी संसद में विपक्ष के नेता डि सिल्वा ने कहा है कि श्रीलंका बिल्कुल दिवालिया हो गया है। अकेले अमेरिका का उसे 7 अरब डालर का कर्ज चुकाना है। चीन के सवा तीन बिलियन डॉलर के कर्जे में दबे श्रीलंका ने अपनी कई लंबी-चौड़ी जमीनें चीन के हवाले कर दी हैं। वह उसे ब्याज भी ठीक से नहीं दे पा रहा है। भारत से कई गुना ज्यादा पैसा चीन वहां खपा रहा है।

वांग यी से राष्ट्रपति गोटबाया ने खुलेआम रियायतें मांगी हैं। चीन की सैन्य मदद भी कई रूपों में श्रीलंका को मिल रही है। हथियार, पनडुब्बियां, प्रशिक्षण आदि क्या-क्या है, जो चीन नहीं दे रहा है।

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना व कराना, सभी की जिम्मेदारी

विश्व कोराना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस महामारी से जूझने के लिए कई स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। पूरा तंत्र सक्रिय कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की बढ़त दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सभी सम्बंधित विभाग के लिए पहली व दूसरी लहर के अनुभव सहायक सिद्ध हो रहे हैं। रात्रि में 10 बजे से 06 बजे तक कर्फ्यू जारी है। सरकार और उसका तंत्र सजग है। लेकिन आमजन महामारी को लेकर सतर्क नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भीड़ वाले क्षेत्रों व केन्द्रों पर व्यवस्था नहीं है। भीड़ यथावत है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी सतर्कता का अभाव है। भीड़ वाले केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है। पहली व दूसरी लहर के दौरान हाथ धोना, एक-दूसरे से दो गज की भौतिक दूरी का अनुपालन बढ़ गया था। महामारी की भयावहता में बहुत लोगों ने अपने परिजन-प्रियजन खोये थे। लेकिन संप्रत्ति तीसरी लहर के प्रकोप से स्वयं बचने और दूसरों को बचाने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। हाथ मिलाने को संक्रमण की एक खास वजह माना जाता है। पहली व दूसरी लहर के दौरान लोगों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों में हाथ मिलाने की लत फिर से पड़ रही है। सारे लोग जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण जानलेवा है। लेकिन आश्चर्य है कि जीवन के नष्ट हो जाने के खतरे के बावजूद

लोग लापरवाही कर रहे हैं।

आपदाएं कष्ट देती हैं। जीवन छीनती हैं। लेकिन तमाम अनुभव भी देती हैं। संप्रति एक नई सामाजिक व्यवस्था आकार ले रही है। पंथिक अंधविश्वासों की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मान्यता बढ़ी है। पंथिक जलसों की भीड़ कम हो रही है। सामाजिक शिष्टाचार बदल रहे हैं। नमस्कार ने हाथ मिलाने की आधुनिक जीवनशैली को विस्थापित कर दिया है। स्वच्छता नया जीवन मूल्य हो रही है। अनावश्यक विदेश यात्राओं के लती पुनः विचार के लिए बाध्य हो रहे हैं। सब जीना चाहते हैं। लेकिन मृत्यु जीवन छीनती है। जीवन की इच्छा और मृत्यु भय से समाज व सभ्यता का विकास हुआ। आदिम मनुष्य का जीवन असुरक्षित था। सामूहिक जीवनशैली में सुरक्षा थी। उसने गुफाओं में रैन बसेरा बनाए। उसने जानवरों के शिकार और आत्म रक्षा के लिए पत्थर के हथियार बनाए। जीने की इच्छा व मृत्यु भय की छाया में आदिम समाज की जीवनशैली का विकास हुआ। आत्मरक्षा की भावना भी सभ्यता के विकास की प्रेरक थी। प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध वीभत्स मृत्यु भय लाते हैं। व्यापक जनहानि वाली आपदाएं जीवन का दृष्टिकोण बदलती हैं। चार्ल्स डारविन प्राकृतिक इतिहास और भूगर्भ शास्त्रीय खोज में विश्व यात्रा पर थे। भूकम्प आया। वह उठे, चक्कर आया, गिरे। उन्होंने इस अनुभव का निष्कर्ष 'जरनल ऑफ रिसर्चेज' में लिखा, 'भूकम्प पुराने से पुराने भावनात्मक सम्बंधों को नष्ट करता है। अल्पकाल में असुरक्षा की ऐसी धारणा बनी जो दीर्घकाल के चिंतन से न पैदा होती।' सामने खड़ी मृत्यु जीवन दृष्टिकोण बदलती है। कोरोना का अनुभव भयावह रहा है। महामारी ने नया अनुभव दिया है। भयावह मौतों ने संसार के प्रति चिंतन का दृष्टिकोण बदल दिया है।

भारत में महाभारत काल में यहां सभा जैसी लोकतंत्री संस्थाएं थीं। वे असफल हुईं। महायुद्ध हुआ। यह राष्ट्रीय आपदा थी। युधिष्ठिर जीत गए लेकिन नरसंहार ने उन्हें व्यथित किया। जीवन का दृष्टिकोण बदला। वे सत्ता सम्हालने को तैयार नहीं थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का भी जीवन दृष्टिकोण बदल गया। कोरोना आपदा में भारत में अन्य देशों की तुलना में बचाव के प्रयत्न ज्यादा सफल हुए हैं। इस आपदा के प्रभाव में संपूर्ण समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सामान्यजन भी गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहे हैं। अब समाज अतिरिक्त संवेदनशील हो गया है। पुलिस बल महामारी के दौरान चिकित्सकों के साथ संग्राम की अग्रिम पंक्ति का सम्मानीय योद्धा बन गया है। उम्मीद है कि तीसरी लहर में भी जनसेवा शैली ऐसी ही रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर का कहर सामने है। सारी दुनिया के राष्ट्रों व राष्ट्राध्यक्षों के लिए चुनौती है। पहली व दूसरी लहर में विकसित देश भी नागरिकों के बचाव में सफल नहीं रहे। अमेरिकी महाशक्ति भी असफल रही। कम्युनिस्ट चीन अपयश का निशाना है ही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के काम की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। वे दुनिया के संवेदनशील नेता होकर उभरे हैं। संप्रति भारतीय राज और समाज दोनों ही संवेदनशील हैं। समाज का व्यक्तित्व अतिरिक्त संवेदनशील रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया की आभासी दुनिया के एक वर्ग में शब्द और अपशब्द का अंतर समाप्त हो गया है। श्लील और अश्लील की विभाजन रेखा समाप्त हो गई है। आश्चर्य है कि इस महामंच पर सक्रिय योद्धाओं के मन संयमी महामारी के साथ जीने वाली नई नहीं हैं। समाज चिंतकों को सोशल मीडिया की प्रवृत्ति के हतोत्साहन के लिए सक्रिय होना चाहिए। विश्व व्यवस्था का चिंतन जारी है।

गांवों में महामारी का प्रकोप कम रहा है। महामारी ने रोग निरोधक क्षमता का प्राचीन भारतीय प्रतीक दोहराया है। आधुनिकतावादी भी तुलसी गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन का काम प्रायः जनअभियान व आन्दोलनों से होता था। महामारी ने समाज का आत्म रूपांतरण किया है। ऐसी उपलब्धियां संजोने योग्य हैं। कालरथ गतिशील है। मृत्यु या जीवन में एक का चयन ही विकल्प है। आनंदमगन जीवन के लिए नई समाज व्यवस्था का सुस्वागतम् जरूरी हैं।

महाभारत के यक्ष प्रश्नों में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि ''दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है- किं आश्चर्यं'' युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया कि ''दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु को जानते हुए भी इस सच्चाई को स्वीकार न करना है।'' युधिष्ठिर ने कहा था कि ''सारे लोग जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, बावजूद इसके ऐसा आचरण करते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे।'' इसी तरह सारे लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से जीवन को खतरा है लेकिन आचरण ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कोरोना महामारी कोई हँसी-मजाक हो। सैनिटाइजेशन लगभग बंद दिखाई पड़ रहा है। भौतिक दूरी भी उपेक्षित है। जागरूक लोगों, वरिष्ठों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और कराएँ। इसके लिए प्रभावी लोकमत का निर्माण भी करें।

विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग जरूरी

हाल ही में संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पूरी दुनिया में भारत के आगे केवल तीन देश हैं- चीन, जापान और स्विटरलैंड। 7 जनवरी को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 632 अरब डॉलर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ऐसे विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के आकार के मद्देनजर देश के आर्थिक और वित्तीय जगत में यह विचार मंथन किया जा रहा है कि देश में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती तथा चीन व पाक से मिल रही रक्षा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों की उपयुक्त मात्रा में खरीदी के लिए विदेशी मुद्रा कोष के एक भाग को व्यय करने की डगर पर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ा जाए। गौरतलब है कि एक ओर जब कोविड-19 के कारण जनवरी 2022 की शुरुआत में भी दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं, तब देश के विशाल आकार के विदेशी मुद्रा भंडार से जहां भारत की वैश्विक आर्थिक साख बढ़ी है, वहीं इस बड़े विदेशी मुद्रा भंडार से देश की एक वर्ष से भी अधिक की आयात जरूरतों की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार देश की अच्छी आर्थिक स्थिति और आकर्षक अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। वस्तुतः विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में देश का तीन दशक पहले का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। वर्ष 1991 में देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। हमारी अर्थव्यवस्था भुगतान संकट में फंसी हुई थी। उस समय के गंभीर हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब दो-तीन हफ्तों की आयात जरूरतों के लिए भी पर्याप्त नहीं था।

उस समय रिजर्व बैंक के द्वारा करीब 47 टन सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रख कर विभिन्न आयात जरूरतों के लिए कर्ज लिया गया था। फिर देश के द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसका उद्देश्य वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ाना रहा। इस नई नीति के पश्चात धीरे-धीरे देश के भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरने लगी। वर्ष 1994 से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। 2002 के बाद इसने तेज गति पकड़ी। वर्ष 2004 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। फिर इसमें लगातार वृद्धि होती गई और 5 जून 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार ने 501 अरब डॉलर के स्तर को प्राप्त किया। इस वर्ष जनवरी 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार का आकार करीब 585 अरब डॉलर को पार कर गया और वर्ष के अंत में यह करीब 635 अरब डॉलर की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। इस समय देश के विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से बढ़ने के तीन प्रमुख आधार हैं- एक, देश से निर्यात बढ़ना। दो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) बढ़ना। तीन, प्रवासियों के द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत के कुल विदेश व्यापार व निर्यात बढ़ने की चमकदार स्थिति बनी है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर 2021 के नौ महीनों के दौरान भारत का निर्यात करीब 303 अरब डॉलर से अधिक रहा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को एफडीआई के प्रवाह ने भी तेजी से बढ़ाया है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में देश में एफडीआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में एफडीआई 19 प्रतिशत बढ़कर 59.64 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान इक्विटी, पुनर्निवेश आय और पूंजी सहित कुल एफडीआई 10 प्रतिशत बढ़कर 81.72 अरब डॉलर हो गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन एजुकेशन तथा वर्क फ्राम होम की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए इंटरनेट के उपयोगकर्ता, देशभर में डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाओं के डिजिटल होने से अमेरिकी टेक कंपनियों सहित दुनिया की कई कंपनियां भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रिटेल सेक्टर के ई-कॉमर्स बाजार की चमकीली संभावनाओं को मुट्ठियों में करने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर एफडीआई के साथ आगे बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अपना निवेश करने के पहले उस देश के शेयर बाजार के परिदृश्य को अच्छी तरह मूल्यांकित करते हैं। ऐसे में इस समय दुनिया के निवेशक भारत के शेयर बाजार की तेजी से बढ़ती हुई ऊंचाई को पूरी तरह महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्ष 23 मार्च 2020 को जो बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स 25981 अंकों के साथ ढलान पर दिखाई दिया था, वह 14 जनवरी को 61223 की ऊंचाई पर बंद हुआ है। यद्यपि पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट रही है, इसके बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा भारत को प्राथमिकता दिए जाने के कई कारण हैं। भारत में निवेश पर बेहतर रिटर्न है। भारतीय बाजार बढ़ती डिमांड वाला बाजार है। भारत के एक ही बाजार में कई तरह के बाजारों की लाभप्रद निवेश विशेषताएं हैं। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नीति के तहत देश में कारोबार को गति देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। निवेश और विनिवेश के नियमों में परिवर्तन भी किए गए हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीयों ने 87 अरब डॉलर की धन राशि स्वदेश भेजी है। चूंकि भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों का 80 से 85 प्रतिशत आयात करता है और इस पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है, ऐसे में पिछले वर्ष 2020 कोरोना की पहली लहर और फिर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से मई 2021 के महीनों में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन के कारण पेट्रोलियम पदार्थों और सोने के आयात में बड़ी कमी आने से विदेशी मुद्रा भंडार से व्यय में कमी आना भी विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण रहा है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के बल पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा बाजार में पूरा दखल देकर वित्तीय अस्थिरता को कम करने और विदेशी बाजारों में रुपए की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाई है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के दखल से अर्थतंत्र में रुपए की तरलता बढ़ी और महामारी के दौरान बाजार में ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिली। अब भविष्य में भी बड़े विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर आरबीआई मुद्रा बाजार में वित्तीय स्थिरता लाने में सक्षम होगा।

लेख

पंचकूला देशभर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 23 व 24 फरवरी को रखेंगे हड़ताल

पंचकूला

केन्द्र सरकार की निजीकरण संबंधी नीतियों के विरोध में आगामी 23 व 24 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी व इंजीनियर दो दिवसीय हड़ताल करेंगे। चंडीगढ़ में भी बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इससे पहले बिजली कर्मचारियों का राष्ट्रीय फेडरेशन 01 फरवरी को चंडीगढ़ में राज्यपाल को बिजली निजीकरण के खिलाफ एक ज्ञापन देंगे।

सोमवार को सुभाष लाम्बा ने बताया कि चंडीगढ़ का बिजली विभाग लगातार मुनाफे में चल रहा है। वर्ष 2020-21 में चंडीगढ़ के बिजली विभाग ने 257 करोड़ का मुनाफा कमाया है। चंडीगढ़ की लाइन हानियां मात्र 09.2 प्रतिशत हैं और चंडीगढ़ का टैरिफ हरियाणा और पंजाब से काफी कम है। ऐसे में लगातार मुनाफा कमाने वाले बिजली विभाग का निजीकरण स्वीकार्य नहीं है और उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

एनसीसीओईईई की ऑनलाइन में मीटिंग में हड़ताल का निर्णय लिया गया है।

मीटिंग की अध्यक्षता ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने की। मीटिंग में ईईएफआई के केओ हबीब, प्रशांत नंदी चौधरी, सुभाष लाम्बा व एस एस सुब्रमण्यम, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के रत्नाकर राव, पद्मजीत सिंह व के अशोक राव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर के आरके त्रिवेदी, अभिमन्यु धनखड़, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज के कृष्णा भोयूर और ऑल इंडिया पावर मेन्स फेडरेशन के समर सिन्हा ने हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के आह्वान पर देश के सभी प्रान्तों के 15 लाख नियमित व 12 लाख अनुबंध बिजली कर्मचारी और इंजीनियर आगामी 23 व 24 फरवरी हड़ताल पर रहेंगे। यह लोग केन्द्र सरकार की निजीकरण नीति का विरोध कर रहे हैं।

हरेरा चेयरमैन ने की राज्यपाल से मुलाकात

चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से सोमवार को हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन के.के.खंडेलवाल ने शिष्टाचार मुलाकात की। खंडेलवाल ने हरेरा द्वारा तैयार की गई ''भगवत गीता डायरी-2022'' भेंट की। दत्तात्रेय ने कहा कि इस डायरी में ज्ञानवर्धक जानकारी है। इससे गीता के उपदेशों का प्रचार-प्रसार होगा।

राज्यपाल ने कहा कि डायरी में वार्षिक कैलेण्डर के साथ-साथ शामिल किए गए पञ्चांग तथा विभिन्न दिवसों को दर्शाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार की डायरी के छापने से जहां हरियाणा के उभरते हुए साइबर सिटी की जानकारी मिलेगी।

हरेरा के चेयरमैन के.के खंडेलवाल ने कहा कि कैलेण्डर के अलावा डायरी के हर पन्ने पर श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक छापे गए हैं। इन श्लोकों के सरल अर्थ बताने के लिए हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।

आज 'साइबर चौपाल' के जरिए युवाओं से जुड़ेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फेसबुक पर साइबर चौपाल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं से रूबरू होंगे। वे शाम सात बजे अपने फेसबुक पेज www.facebook.com/dchautala पर इस कार्यक्रम में युवाओं से 75 प्रतिशत लोकल रोजगार कानून के विषय पर चर्चा करेंगे।

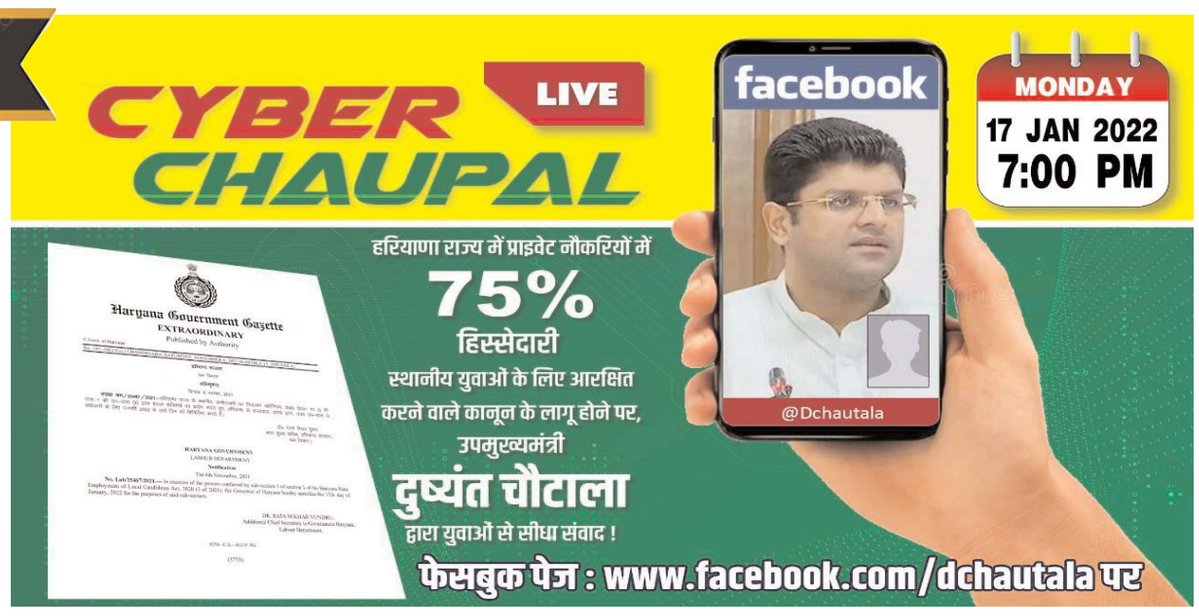

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फेसबुक पर साइबर चौपाल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं से रूबरू होंगे। वे शाम सात बजे अपने फेसबुक पेज www.facebook.com/dchautala पर इस कार्यक्रम में युवाओं से 75 प्रतिशत लोकल रोजगार कानून के विषय पर चर्चा करेंगे। उपमुख्यमंत्री इसी विषय पर मंगलवार को 12 बजे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का भी जवाब देंगे।हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं के सुनहरे भविष्य की दिशा में एक मजबूत व बड़ा कदम बढ़ाते हुए 15 जनवरी 2022 से 75 प्रतिशत लोकल रोजगार कानून प्रभावी तौर पर लागू कर दिया गया है।

अब राज्य में सभी प्राइवेट सेक्टर, संस्थान, ट्रस्ट, सोसायटी, उद्योगों व कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। यह जेजेपी का प्रमुख चुनावी वादा और घोषणापत्र का सबसे पहला वादा था, जिसे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरा किया है।

केंद्रीय बजट 2022-23

श्री कमलजीत सिंह पंछी अध्यक्ष चंडीगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन सेक्टर -17 चंडीगढ़ ने भारत की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन को केंद्रीय बजट में विचारार्थ कुछ सुझाव भेजे।

1. बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष पैकेज,
2. व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाएं जो सरकार के लिए राजस्व एकत्र करने का मुख्य स्रोत हैं।
3. चंडीगढ़ के व्यापारियों के लिए वैट मामलों (एकमुश्त निपटान) में डीम्ड असेसमेंट।
4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा।
5. कोरोना में जान गंवाने वाले व्यापारी परिवारों के लिए राहत पैकेज।

हम चंडीगढ़ के व्यापारी आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया उपरोक्त सुझाव पर विचार करें।

डीएवी,नारायणगढ़ का वंशज गर्ग हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित

डीएवीनारायणगढ़ का वंशज गर्ग हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित डीएवी(सी.सै.)पब्लिक विद्यालय के बारहवीं के छात्र वंशज गर्ग ने जूनियर ग्रुप पावर लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए डेड लिफ्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए डेड लिफ़्ट में 160 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया ।

डीएवीनारायणगढ़ का वंशज गर्ग हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित डीएवी(सी.सै.)पब्लिक विद्यालय के बारहवीं के छात्र वंशज गर्ग ने जूनियर ग्रुप पावर लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए डेड लिफ्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए डेड लिफ़्ट में 160 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया । यह प्रतियोगिता 7 जनवरी 2022-09 जनवरी 2022 तक असंध करनाल में 100 व्व रॉ इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया की एक तरफ़ से आयोजित हुई । विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आर.पी .राठी ने वंशज और उसके अभिभावकों को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा की वंशज ने अथक परिश्रम और प्रयास एवं मार्गदर्शन द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर जीत का परचम लहराया है ।प्रचार्य ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए वंशज गर्ग को प्रोत्साहित किया और अप्रैल माह में दुबई में होने वाली प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ दी ।

पंजाब में अब 20 फरवरी को होगा मतदान - चुनाव आयोग

केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिये मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया है। राज्य में अब 14 के बजाय 20 फरवरी को मतदान होगा।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने रविदास जयंती के कारण मतदान की तारीख में बदलाव किया है। पहले राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना तय था। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा समेत कई दलों और धार्मिक संगठनों ने आयोग से मतदान की तारीख में बदलाव की मांग की थी। आयोग ने इसको ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को मतदान की तारीख तय की है। उनका तर्क था कि 16 फरवरी को रविदास जयंती की वजह से राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी जाते हैं। इस कारण वह मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की इस मांग को ध्यान में रखकर आयोग ने मतदान की तारीख का फैसला किया है। इस क्रम में आयोग ने नामांकन की तारीखों में भी बदलाव किया है। 25 जनवरी को अधिसूचना जारी की जायेगी। नामांकन की अंतिम तिथि एक फरवरी और मत पत्रों की जांच दो फरवरी को होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख चार फरवरी तय की गई है और मतदान 20 फरवरी को संपन्न किया जायेगा

देवास मल्टीमीडिया बंद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी। संप्रग सरकार के कार्यकाल में देवास मल्टीमीडिया ने इसरो से जुड़े अंतरिक्ष कारपोरेशन के साथ भारत में सेटेलाइट सेवा मुहैया कराने के लिए करार किया था। लेकिन अंतरिक्ष कारपोरेशन ने पाया कि देवास मल्टीमीडिया इस काम में फर्जीवाड़ा कर रहा है। इस आधार पर अंतरिक्ष कारपोरेशन, देवास मल्टीमीडिया को बंद कर दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी चली गई।एनसीएलटी ने अंतरिक्ष की दलील को सही ठहराते हुए उसके पक्ष में फैसला दिया जिसे देवास मल्टीमीडिया ने एनसीएएलएटी में चुनौती दी। एनसीएएलएटी ने अंतरिक्ष के हक में फैसला दिया जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। देवास और अंतरिक्ष के बीच वर्ष 2005 में सेटेलाइट सेवा को लेकर करार हुआ था जिसे संप्रग सरकार ने वर्ष 2011 में रद किया। जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशकों से संचालित होने वाली देवास मल्टीमीडिया के फर्जीवाड़े को समझने में तब की संप्रग सरकार को पांच साल से अधिक समय लग गए। उस समय 2जी मामला भी सामने आ गया था, इसलिए देवास के साथ करार को आनन-फानन रद कर दिया गया। इतना अधिक समय लेने की वजह से ही देवास मल्टीमीडिया के विदेशी निवेशकों को भारत सरकार के खिलाफ कनाडा की अदालत में मुकदमा दायर करने का मौका मिल गया जहां पिछले साल एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की विदेश में स्थित संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए गए।

हालांकि इस माह कनाडा की अदालत ने अपने ही फैसले पर रोक लगाते हुए भारत सरकार को राहत दे दी है।अब जानकार यह सवाल उठा रहे हैं कि देवास मल्टीमीडिया के साथ सेटेलाइट सेवा के लिए बिना जांच- परख के करार क्यों किया गया। दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि जब देवास के फर्जीवाड़े के आधार पर दोनों के बीच करार को रद किया गया तो फिर उसी समय में देवास के खिलाफ एनसीएलटी में सरकार क्यों नहीं गई।बीजेपी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में सीबीआई से इस मामले की जांच कराई गई। फिर जाकर इस मामले का पर्दाफाश हुआ। सोमवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देवास मल्टी मीडिया का गठन अंतरिक्ष कारपोरेशन के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े के उद्देश्य को लेकर किया गया था।

देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी। संप्रग सरकार के कार्यकाल में देवास मल्टीमीडिया ने इसरो से जुड़े अंतरिक्ष कारपोरेशन के साथ भारत में सेटेलाइट सेवा मुहैया कराने के लिए करार किया था।

फतेहाबाद के टोहाना में डांगरा रोड स्थित किसान रेस्ट हाउस में श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। (27 जनवरी, 2022)

फतेहाबाद के टोहाना में डांगरा रोड स्थित किसान रेस्ट हाउस में श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बच्चों के लिए अनिवार्य टीकाकरण को रद्द करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र के उस निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण के बाद कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के बाद से बहुत ही कम समय में कई बच्चों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डेनियेलु कोंडीपोगु नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई है।याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उनके बच्चों की मृत्यु कोविड वैक्सीन लेने के बाद विभिन्न जटिलताओं के कारण हुई थी। याचिका बच्चों की मौत और इसी तरह की अन्य मौतों की जांच के लिए एक विशेषज्ञों समूह गठित करने की मांग उठाई गई है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर इस अदालत को रिपोर्ट देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट द्वारा मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि ÷यह बहुत परेशान करने वाला है क्योंकि जनादेश अवैध है और केंद्र सरकार के निर्देश के विपरीत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मंत्रालय की ओर से 28 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दायर काउंटर हलफनामे में स्पष्ट किया जा रहा है।

ग्रामीणों ने किया विधायक सिहाग के आवास का घेराव

- **पिछले 24 दिनों से ठिठुरती ठंड के बीच गांव तलवंडी के राणा के बस अड्डे पर हिसार से तलवंडी राणा के वैकल्पिक मार्ग की मांग पर धरने पर डटे ग्रामीणों ने सोमवार को बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग का हिसार के सेक्टर-15 स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचकर घेराव किया।**
- **विधायक का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों के साथ आज भूख हड़ताल पर बैठे पांच ग्रामीण भी साथ थे। ग्रामीणों का कहना था कि बरवाला हलके के विधायक व प्रदेश में जजपा-भाजपा गठबंधन की सरकार होने के चलते ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग दिलवाना विधायक की जिम्मेवारी है**

पिछले 24 दिनों से ठिठुरती ठंड के बीच गांव तलवंडी के राणा के बस अड्डे पर हिसार से तलवंडी राणा के वैकल्पिक मार्ग की मांग पर धरने पर डटे ग्रामीणों ने सोमवार को बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग का हिसार के सेक्टर-15 स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचकर घेराव किया। विधायक का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों के साथ आज भूख हड़ताल पर बैठे पांच ग्रामीण भी साथ थे। ग्रामीणों का कहना था कि बरवाला हलके के विधायक व प्रदेश में जजपा-भाजपा गठबंधन की सरकार होने के चलते ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग दिलवाना विधायक की जिम्मेवारी है, इसलिए वे ग्रामीणों को तुरंत यह मार्ग दिलवाएं। विधायक जोगीराम सिहाग ने ग्रामीणों की बात को गंभीरता से सुना और तुरंत डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फोन मिलाकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत करवाया जिस पर उन्होंने आगामी 24 तारीख को हिसार आने पर ग्रामीणों की समस्या सुनने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा कि यदि आगामी 24 तारीख को उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो विधायक जोगीराम सिहाग के आवास के समक्ष भी एक धरना शुरू कर देंगे। ग्रामीणों का प्रतिनधित्व कर रहे ओपी कोहली ने बताया कि इतनी भारी ठंड में पिछले तीन सप्ताह से ग्रामीण सडक़ पर बैठे हैं लेकिन सरकार लगातार ग्रामीणों की मांग की उपेक्षा कर रही है जबकि इस बारे में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधायक, डिप्टी स्पीकर सभी को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। धरने पर पिछले दो दिनों से पांच ग्रामीण क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं।

धरनास्थल पर भारी ठंड के चलते गत दिवस चार ग्रामीणों की तबीयत भी बिगड़ गई जिनमें त्रिलोक पंच, होशियार सिंह सिवाच जुगलान, महावीर बटार व लीलाराम कोहली शामिल हैं लेकिन इसके बावजूद वे उपचार लेकर धरने पर बैठे हैं।

इस अवसर पर एडवोकेट ओपी कोहली के अलावा युवा कांग्रेस के हलका अध्यक्ष मनोज कोहली, डॉ. सुरेश, महाबीर बटार, त्रिलोक पंच, जयपाल गुरी, सरपंच महेन्द्र कोहली, नंबरदार राधे श्याम कोहली, महाबीर जांगड़ा, मनीराम जांगड़ा, मास्टर सूबे सिंह, राजेश गोरसी, प्रकाश हाकला, धर्मपाल बटार, डॉ. सीताराम जांगड़ा, बहादुर पंच, कृष्ण मुक्कड़, सतबीर सैन, पवन हाकला, मखन रोलन, ओमबीर पंच, सत्यवान चोपड़ा, सुभाष मनकस, सुरेंद्र कोहली, सूबे सिंह सैन, जोगिंद्र पंच, संजय पंच आदि मौजूद रहे।

भाजपा राज में खुले फरीदाबाद के विकास के द्वार कृष्णपाल गुर्जर

- **केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को एत्मादपुर से मवई तक के रास्ते में बनने वाले 4 पुलों का शिलान्यास किया। इनकी अनुमानित लागत 16 करोड़ 92 लाख रुपये है।**
- **उन्होंने कहा कि एत्मादपुर से मवई तक ऐसे चार पुल बनेंगे और जिससे लोगों का आवागमन सुलभ होगा।**
- **जाम और हादसों में कमी आएगी। गुर्जर ने कहा कि भाजपा राज में फरीदाबाद के विकास के द्वार खुले हैं।**

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को एत्मादपुर से मवई तक के रास्ते में बनने वाले 4 पुलों का शिलान्यास किया। इनकी अनुमानित लागत 16 करोड़ 92 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि एत्मादपुर से मवई तक ऐसे चार पुल बनेंगे और जिससे लोगों का आवागमन सुलभ होगा। जाम और हादसों में कमी आएगी। गुर्जर ने कहा कि भाजपा राज में फरीदाबाद के विकास के द्वार खुले हैं।

उन्होंने कहा कि आगरा कैनाल पर पुल बनाए हुए हैं और उसी तरह यह चारों फोरलेन के पुल बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच है जिसकी वजह से इन छोटी पुलिया पर चार लाइन का पुल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी यह सडक़ दो लाइन की है लेकिन हम पुल चार लाइन के बनवा रहे हैं क्योंकि हमारी सोच आगे के 20 साल को सोच कर चल रही है।

गुर्जर कहा कि आने वाले समय में जब यह सड़क फोरलेन बनेगी तो पुल तो पहले से ही फोरलेन बन चुके होंगे। उन्होंने कहा कि इतने सालों से यहां कांग्रेस का राज था तो उनके राज में पुल क्या उन्होंने एक पुर्जा तक नहीं लगवाया। अब इस इलाके के लिए नया हाइवे निकल गया है और यह रोड आने वाले समय में फोरलेन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां से नोएडा, दिल्ली सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर रह जाएंगे। अगले 2 साल में इसी हाईवे को जेवर से जोड़ देंगे ताकि आप आधे घंटे में जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा एक भी शहर नहीं है जिसके दोनों तरफ हाईवे हो। आप सब के आशीर्वाद से देश में नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार बनी है और आप लोगों ने मुझे यहां से सांसद बनने का मौका दिया। कांग्रेस के समय का फरीदाबाद और आज के समय का फरीदाबाद देख ले। उन्होंने कहा कि पहले मथुरा रोड की सूरत क्या थी और आज उसकी सूरत देख ले। यहां एक नया नेशनल हाईवे आपके बराबर में बनना है जो डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शहर में दो-दो हाइवे होंगे और एक तीसरा हाइवे और पास कराया गया है जो यहां से जेवर एयरपोर्ट तक सिर्फ आधे घंटे में पहुंचाएगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट जाओगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे और जेवर एयरपोर्ट जाने में सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा यह मेरा वादा है। उन्होंने कहा कि जब नियत होती है तब नीतियां बनती हैं योजनाएं बनती हैं तभी काम होते हैं।

हर्षोल्लास और परम्परा अनुसार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह-मुकुल।

कुरुक्षेत्र उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास और परम्परा अनुसार मनाया जाएगा। इस समारोह का आयोजन पुलिस लाईन कुरुक्षेत्र के प्रांगण में किया जाएगा और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना की जाएगी और इस विषय को जहन में रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों को अधिकारी उनके घर जाकर मान-सम्मान करेंगे।

उपायुक्त मुकुल कुमार सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त मुकुल कुमार ने गणतंत्र दिवस समारोह को कोविड-19 की गाइडलाइन को जहन में रखते हुए बेहतर आयोजन के बारे में फीडबैक रिपोर्ट हासिल की और समारोह के दौरान सभी एचओडी को उपस्थित रहने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहीदी स्मारक और आसपास के क्षेत्र तथा पुलिस लाइन कार्यक्रम स्थल के आसपास साफ-सफाई की व्यवस्था करने का काम पूरा किया जाए। इसके लिए नगर परिषद व हुडा के कार्यकारी अधिकारी विशेष फोकस रखेंगे। दोनों स्थलों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था तथा बिगुल बजाने के लिए संतरी और ध्वजारोहण के लिए ध्वज का प्रबंध करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परेड में इस वर्ष पुलिस की तरफ से टुकडियों का प्रबंध किया जाएगा, जिसमें, पुलिस के जवानों की 2 टुकड़ी, महिला पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड की टुकड़ी भी शामिल होगी। इसके लिए डीएसपी मुख्यालय परेड को तैयार करेंगे ताकि 24 जनवरी को फाईनल रिहर्सल में परेड शानदार प्रदर्शन कर सके।उन्होंने कहा कि निमंत्रण कार्ड, शहर की सफाई व्यवस्था, पंडाल की साज-सज्जा, रंगोली, कार्यक्रम स्थल के आसपास स्वागत द्वार, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सिविल सर्जन की तरफ से सैनिटाइजर, मास्क का प्रबंध किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पीटी शो का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ कार्यक्रम में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य सभी के लिए मास्क लगाना व वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाना है, वह अपने नाम का अनुमोदन शीघ्र अति शीघ्र देना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डा. अंशु सिंगला, एएसपी कर्ण गोयल, सीटीएम चंद्रकांत कटारिया, डीडीपीओ प्रताप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

लिगामेंट इंजरी के सफल इलाज के बाद पुन खेलने में समर्थ होंगे खिलाड़ी-डॉ. अमनप्रीत।

करनाल विर्क अस्पताल एवं सरबत दा भला ट्रस्ट की ओर से घुटने, कूल्हे एवं लिगामेंट संबंधी इंजरी को लेकर निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विर्क हॉस्पिटल में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक लगाया गया। जिसमें मरीजों की निशुल्क जांच की गई वहीं जरूरतमंद मरीजों का एक्सरा भी किया गया। जानकारी देते हुए प्रवेश गाबा और हरदीप वालिया ने बताया कि शिविर में अधिकतर मरीज स्पोर्ट्स इंजर्ड खिलाड़ी पहुंचे। शिविर में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डा. बलबीर विर्क व स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ डा. अमनप्रीत सिंह व डा. विकास गोयल, डा. संजीव ने मरीजो की जांच करते हुए बताया कि वे जमाने चले गए जब खिलाड़ियों को खेल के मैदान में लगी चोट के कारण उनका वहीं से करियर खत्म हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है आज हालात बदल गए है। लिगामेंट-एसीएल के टूटने के बाद इलाज करवाकर खिलाड़ी पुन: मैदान में खेलने के लिए तैयार हो जाते है। उन्होंने बताया कि खेल के दौरान लगने वाली चोटों में घुटनों के सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट एसीएल टूटने का इलाज अब आर्थोस्कोपी के जरिए अतीत की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो चुका है। डा. बलबीर विर्क व स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ डा. अमनप्रीत सिंह ने स्पोर्ट्स इंजर्ड खिलाड़ियों को जानकारी देते हुए बताया कि लिगामेंटस रस्सी नुमा तंतुओं के ऐसे समूह हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस कारण जोड़ सुचारू रूप से कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि एसीएल सर्जरी घुटने को स्थिरता प्रदान करती है। फुटबॉल,बास्केटबॉल और स्कीइंग आदि में जब घुटना ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि लिगामेंट खींचते हुए टूट जाता है।

निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण 15 जनवरी से हुआ कानूनी रूप में लागू - पदम सिंह दहिया

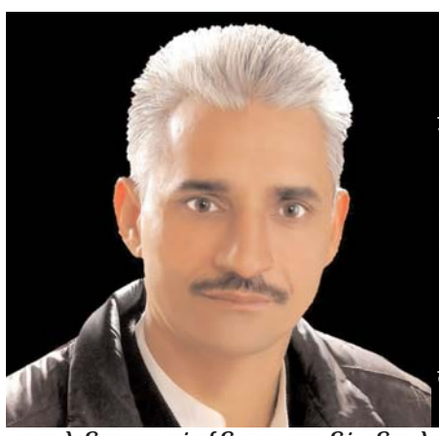

जजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया ने उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से यह कानून हरियाणा में लागू हो चुका है।

जजपा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया ने कहा कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा कर दिया है, जिसका युवाओं ने खुले दिल से स्वागत किया है।

जजपा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया ने कहा कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा कर दिया है, जिसका युवाओं ने खुले दिल से स्वागत किया है। इसके लिए युवा खुशी से उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

जजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया ने उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से यह कानून हरियाणा में लागू हो चुका है। इस नए कानून से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी करके रोजगार प्राप्त करना हर युवा का एक सपना होता है और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत का कानून हरियाणा के युवाओं के लिए बनने से अब रोजगार प्राप्त करना सहज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी कुशलता के मुताबिक प्राईवेट कम्पनीयों में नौकरियां मिल सकेगी और वे जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकेंगे।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत रोजगार देने संबंधित बिल को मंजूरी दे दी गई है।

लेख

श्रीराम मंदिर में पानी निकासी न होने श्रद्धालु आहत

जयति-जयति हिंदू महान संगठन व राम मंदिर परिसर के पुजारी व श्रद्धालुओं ने सोमवार को पुराने राम मंदिर में गंदे पानी की निकासी को लेकर रोष जताया है। श्रद्धालुओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर इस धरोहर को बचाने की अपील की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर से जींद के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में इस मंदिर के रखरखाव को लेकर विशेष कदम उठाए जाएं। अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो श्रद्धालु व हिंदू संगठन आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

जयति-जयति हिंदू महान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अतुल चौहान ने बताया कि रानी तालाब के साथ लगते लगभग 300 वर्ष पुराने राम मंदिर गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है। यह मंदिर रानी तालाब के साथ ही बना था। रानी तालाब में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। प्राचीन होने के साथ साथ यह मंदिर अपनी अलग महत्वता भी रखता है। अब यह मंदिर नीचा पड़ गया है जिसके कारण मंदिर परिसर में पानी भरा रहता है।

पिछले दिनों हुई बारिश से सारा मंदिर जलमग्न हो गया था। जिसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। पहले यह पानी रानी तालाब में जाता था लेकिन अब यह पाइप लाइन किसी कारण से बंद हो गई है। यहां हर रोज सैंकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। पानी भरा होने के कारण यहां श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हों, प्रशासन को इसका ख्याल रखना चाहिए। श्रद्धालुओं ने मांग की कि पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि दो दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। इस मौके पर विनय गोयल, प्रदीप शर्मा, इंद्रजीत, कपिल शर्मा, सोमबीर पांचाल, मनोज भट्ट, गोल्डी वलेचा, लक्की मोंगिया आदि लोग मौजूद रहे।

रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने किया राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान

हरियाणा कर्मचारी महासंघ, एटक व ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 23 व 24 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी यूनियन भी शामिल होगी।

हड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

रोडवेज कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान ओमप्रकाश ग्रेवाल, महासचिव जयवीर घणघस व हिसार डिपो प्रधान राजबीर दुहन ने सोमवार को कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी नीति अपनाकर व वादा खिलाफी कर कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। इसी के चलते कर्मचारियों ने 23-24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में भारी गुस्सा है।

प्रदेश की सरकार ने बार-बार कर्मचारियों की लंबित मांगों को नाजायज मानते हुए रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सरकार ने मानी गई मांगों को लागू करने की बजाए कर्मचारियों को पहले से मिल रही सुविधाएं छीन कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।

उन्होंने 23-24 फरवरी हड़ताल की प्रमुख मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विभागों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करना योग्यता के आधार पर चालक को तकनीकी निरीक्षक के पद पर प्रमोट करना, 1992 से लेकर 2002 तक के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना, बकाया बोनस का भुगतान करना, निजी बसें ठेके पर लेने की नीति रद्द करना, अनुकंपा अधिनियम 1964 को पहले की भांति लागू करने की मांगे शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति में लगाई गई शर्तें हटाने,

कोरोना महामारी से मृतक रोडवेज कर्मचारियों के परिवारों को एक्सग्रेसिया बीमा पॉलिसी के तहत 50 लाख रुपये मुआवजा देने, वेतनमान अपग्रेड करने, परिचालक व लिपिकों का 35400 वेतनमान अपग्रेड करने सहित अन्य कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, सभी कर्मचारियों को 5000 रुपये जोखिम भत्ता देने, कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, रोडवेज के बेड़े में 10 हजार बसें शामिल करना, परिवहन समिति की बसों को लंबे रूटों पर परमिट देने की नीति को रद्द करना भी मांगों में शामिल है।

हिसार डिपो प्रधान राजबीर दुहन ने कहा कि एटक व ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने वाली इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए रोडवेज कर्मचारियों से संपर्क शुरू कर दिया गया है। उन्हें केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों से अवगत करवाते हुए मांगों व समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा।

3 ग्राम हेरोइन समेत एक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

ओढ़ा पुलिस ने गत रात्रि एक युवक को 3 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया है। एसआई जय सिंह के अनुसार वह गश्त के दौरान गांव बनवाला में घुकांवाली बस स्टैंड पर पुलिस पार्टी के साथ मौजूद था कि इतने में एक व्यक्ति गांव की तरफ से आता दिखाई दिया।

जो कि पुलिस पार्टी को देख कर वापस मुड़ने लगा तो शक के आधार पर उसे काबू कर लिया।

जिसकी पहचान दारा सिंह पुत्र शंकर लाल निवासी बनवाला के रूप मे हुई। पुलिस ने राजपत्रित अधिकारी विक्रमजीत प्रिंसिपल की उपस्थिति में तलाशी ली तो उसके कोट की दाहिनी जेब में से 3 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एएसआई जय सिंह ने दारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश कर दिया।

स्वामी मुद्रक प्रकाशन संपादक : कोरल ने इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 पंचकुला,हरियाणा से छपवा कर कार्यालय स407/16 पंचकुला 134108 हरियाणा से मुर्दित किया।

Website : www.demokraticfront.com, E-mail : democraticfront2021@gmail.com